

प्रकाशनार्थ

पटना, 15 फरवरी। सूचना के दौर में आंकड़े हर जगह उपलब्ध हैं और अत्यंत तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के देश कृषि पर शासन और अनुसंधान के प्रचार-प्रसार, दोनों लिहाज से आंकड़े एकत्र करते हैं। अभी कृषि के बारे में हमें काफी अधिक जानकारी प्रायः राष्ट्रीय सांख्यिकी अभिकरणों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय द्वारा कराए गए पुख्ता सर्वेक्षणों से मिलती है। हालांकि शुरुआत के लिए ऐसी जानकारी उपयोगी होती है लेकिन उनके साथ अनेक बड़ी चुनौतियां जुड़ी होती हैं जिनमें प्रतिनिधित्व, बारंबारता और निस्संदेह उपलब्धता भी शामिल हैं। एक अन्य समस्या यह है कि आंकड़े इकट्ठा करने की प्रविधियों में काफी अंतर हो सकता है। अतः नीति निर्माण के लिए चीजों को समझने और उसमें सुधार करने के लिए आंकड़ों के इन स्रोतों पर पूरी तरह भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के भारतीय कृषि सांख्यिकी शोध संस्थान (आइएएसआरी) और आद्री के साथ मिलकर आइजीसी (इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर) इंडिया ने कृषि संबंधी आंकड़ों पर “कृषि में साक्ष्य निर्माण : आंकड़ा प्रणालियों की समीक्षा और उनके सकारात्मक प्रभाव” विषयक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य यह समझना था कि हम आंकड़ों को कैसे समझ सकते हैं और निर्णय लेते समय उनका लाभ कैसे ले सकते हैं।

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. विकास रावल ने भारत में कृषि सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न ताकतों और कमजोरियों पर मुख्य व्याख्यान दिया। बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार ने इस बात को रेखांकित किया कि आंकड़ों के संग्रहण में दिन-प्रतिदिन सुधार हो रहा है। बिहार सरकार ने भी अपने किसानों का निबंधन शुरू कर दिया है और अभी तक 51 लाख किसान निर्बंधित किए जा चुके हैं।

बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग की सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने बताया कि गाय-भैंस, बकरी और मुर्गियों से संबंधित आंकड़े प्रभावी नीतिगत निर्णय के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित कुछ चुनौतियों और व्यवधानों का भी प्रमुखता से उल्लेख किया।

आद्री के सदस्य सचिव तथा आइजीसी के बिहार के प्रमुख डॉ. शैबाल गुप्ता ने उद्घाटन भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि हम सूचना के युग में रह रहे हैं जिसमें आंकड़े हर जगह उपलब्ध हैं, नीति निर्माताओं को साक्ष्यों कालगातार उपयोग करना चाहिए।

कार्यशाला से एक चिंता यह उभरी कि अच्छी गुणवत्ता वाले आंकड़ों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है।

भारतीय कृषि सांख्यिकी शोध संस्थान (आइएएसआरी) के निदेशक डॉ. लाल मनोहर भर ने अपनी टिप्पणियों में उल्लेख किया कि नमूना सर्वेक्षणों और कृषि संबंधी आंकड़ों के संग्रहण तथा विश्लेषण में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए।

भारतीय कृषि सांख्यिकी शोध संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. वी रामासुब्रामनियन और वैज्ञानिक डॉ. कॉस्तुभ ने भारत में कृषि संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण और निर्णय लेने में प्रयुक्त विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियों पर प्रस्तुतियां दीं।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आइएफपीआरआइ) के शोध अध्येता डॉ. अंजनी कुमार ने कृषि आंकड़ा प्रणालियों की समीक्षा और उनके सकारात्मक प्रभाव पर होने वाले विचार-विमर्श का संचालन किया। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के डीईएस की उप-निदेशक निधि सतीजा और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी श्री अजयानंद झा ने कृषि संबंधी आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा ली गई विभिन्न पहलकदमियों के बारे में जानकारी दी।

आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने धन्यवाद ज्ञापन किया और रेखांकित किया कि आंकड़ा प्रणालियों में, खास कर राज्य स्तर पर अधिकांश समस्याएं संसाधनों की कमी के कारण आती हैं।

अंजनी कुमार वर्मा